Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

03 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनरक्षक परियोजना और 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के शुभारंभ के साथ गुजरात की दो दिवसीय यात्रा का समापन किया।

30 और 31 अगस्त, 2025 के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, ने गुजरात के अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों का दो दिवसीय प्रभावशाली दौरा किया। इस यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, जनसंपर्क और आपातकालीन सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और राजनीतिक आधारभूत ढाँचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उद्घाटन शामिल थे।

• अमित शाह 30 अगस्त की शाम अहमदाबाद पहुँचे और तुरंत शहर के जोधपुर और वस्त्रपुर इलाकों में आयोजित दो सार्वजनिक गणेश महोत्सव समारोहों में शामिल हुए। इन कार्यक्रमों ने सांस्कृतिक परंपराओं से उनके जुड़ाव और स्थानीय मतदाताओं के प्रति उनके आकर्षण को और पुख्ता किया, जिससे त्योहारों के मौसम में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

• 31 अगस्त को, गृह मंत्री ने "जनरक्षक परियोजना" की शुरुआत की, जो एक प्रमुख जन सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य 112 एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू करके राज्य भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना है। इस पहल के तहत, शाह ने 500 'जनरक्षक' वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिनका उद्देश्य पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करना है।

• यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया गुजरात दौरे के तुरंत बाद हुआ है और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति पर आंतरिक चर्चाओं के साथ मेल खाता है। विश्लेषक शाह के इस दौरे को व्यापक चुनावी तैयारियों का हिस्सा मान रहे हैं, जो गुजरात में विधानसभा चुनावों से पहले रणनीतिक कदमों का संकेत है।

Key Points:-

(i) अमित शाह के दौरे ने भाजपा के प्रदर्शन-आधारित शासन और दक्षता पर ज़ोर दिया। राज्यव्यापी आपातकालीन सेवा शुरू करके और उत्सवों में लोगों तक पहुँच बनाकर, गृह मंत्री ने कल्याणकारी हस्तक्षेपों और चुनावी प्रचार-प्रसार के बीच संतुलन बनाया—जिससे प्रशासनिक विश्वसनीयता और स्थानीय स्तर पर तालमेल दोनों का निर्माण हुआ।

(ii) जनरक्षक बेड़े और 112 आपातकालीन नंबर के साथ, एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया की ओर एक बदलाव का संकेत मिलता है। इस परियोजना से गुजरात की आपदा और संकट प्रबंधन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही यह व्यापक शहरी आपातकालीन समाधानों के लिए एक आदर्श के रूप में भी काम करेगी।

(iii) एक मज़बूत आपातकालीन बुनियादी ढाँचे का उद्घाटन करके और जीवंत सांस्कृतिक समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, अमित शाह ने प्रशासनिक कार्रवाई को लोगों से जुड़ाव के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा। उनकी उपस्थिति ने राजनीतिक परिवर्तन से पहले राज्य में जन कल्याण, क्षेत्रीय पहुँच और रणनीतिक लामबंदी के प्रति संघीय सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

2. WaveX और IICT मुंबई ने AVGC-XR स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मीडिया टेक इनक्यूबेटर लॉन्च किया।

अगस्त 2025 में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की एक पहल, वेवएक्स ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT), मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साझेदारी में, मीडिया टेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर लॉन्च किया। यह इनक्यूबेटर पूरे भारत में एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) स्टार्टअप्स को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **मीडिया टेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर दो चरणों वाले मॉडल पर काम करेगा, अर्थात् सक्रिय चरण और निष्क्रिय चरण, ताकि उच्च-संभावित उद्यमों को संरचित सहायता प्रदान की जा सके। सक्रिय चरण के दौरान, स्टार्टअप्स को व्यावसायिक मॉडलिंग, धन उगाहने, उत्पाद विकास, मीडिया विनियमन मार्गदर्शन, और OTT (ओवर द टॉप), VFX (विज़ुअल इफेक्ट्स), VR (वर्चुअल रियलिटी), गेमिंग, एनीमेशन और पोस्ट-प्रोडक्शन में सैंडबॉक्स परीक्षण के अवसर प्राप्त होंगे।**

- **इनक्यूबेटर के निष्क्रिय चरण में वेव्स बाज़ार के माध्यम से वैश्विक प्रदर्शन, साथ ही मार्गदर्शन के अवसर और उद्योग नेटवर्किंग सत्र शामिल होंगे। इससे स्टार्टअप्स को अपने प्रारंभिक इनक्यूबेशन चरण से आगे दीर्घकालिक दृश्यता और निवेशक पहुँच सुनिश्चित होगी।**

- **यह इनक्यूबेटर अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रदान करेगा, जिनमें को-वर्किंग स्पेस, ऑडियो-विज़ुअल/डिजिटल लैब, हाई-स्पीड लैन/वाई-फाई, होस्टिंग सर्वर और अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS), गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की क्लाउड सेवाएँ शामिल हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और मेटा जैसी तकनीकी दिग्गजों के साथ वैश्विक साझेदारी से मार्गदर्शन, निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त होगी।**

Key Points:-

(i) पहले बैच में 15 स्टार्टअप शामिल होंगे, जिन्हें IICT मुंबई में वस्तु एवं सेवा कर (GST) सहित ₹8,500 के मासिक शुल्क पर इनक्यूबेट किया जाएगा। स्टार्टअप्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रत्यक्ष देखरेख में तिमाही-आधारित समीक्षा और मार्गदर्शन भी मिलेगा।

(ii) पहले बैच के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 सितंबर, 2025 है, जो भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एवीजीसी-एक्सआर पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रमुख ऊष्मायन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करता है।

3. IEPFA ने वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निवेशक दीदी चरण II का शुभारंभ किया।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने 8-9 अप्रैल, 2025 को "निवेशक दीदी" कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ साझेदारी की। इस विस्तार का उद्देश्य पूरे भारत में ग्रामीण और वंचित महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन और शिक्षा को गहरा करना है।

- **चरण II उस पहल का विस्तार करता है जिसे पहली बार 2022 में लॉन्च किया गया था, जो चरण I की सफलता पर आधारित है - जहां पूरे भारत में IPPB वित्तीय साक्षरता शिविरों में 55,000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया और उनमें से लगभग 60% आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग की महिलाएं थीं, जिनमें से दो-तिहाई दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आई थीं।**

- **IEPFA और IPPB के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoA) 8 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया, जो ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय कौशल से लैस करने के प्रयासों को रणनीतिक रूप से गहन बनाने का प्रतीक है।**

- **चरण II में देश भर में 4,000 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविरों की स्थापना का प्रावधान है, जिनका नेतृत्व लगभग 40,000 प्रशिक्षित महिला डाक कर्मचारी करेंगी - जिन्हें "निवेशक दीदी" कहा जाएगा - जो सामुदायिक वित्तीय शिक्षकों के रूप में काम करेंगी।**

Key Points:-

(i) इन शिविरों का पाठ्यक्रम जिम्मेदार निवेश, बचत की आदतों, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग उपकरण और धोखाधड़ी को रोकने के उपायों पर केंद्रित है, जिससे सूचित धन प्रबंधन और सुरक्षित डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

(ii) इस कार्यक्रम का नेतृत्व और समर्थन IEPFA की CEO और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता शाह अकेला और IPPB के मुख्य महाप्रबंधक एवं CSMO गुरशरण राय बंसल द्वारा किया गया। दोनों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थानीय महिलाओं को वित्तीय प्रभावक के रूप में सशक्त बनाने से समुदाय-व्यापी प्रभाव पैदा होता है।

(iii) यह सहयोग समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है, जो वित्तीय साक्षरता अंतराल को पाटने और देश भर में हर दरवाजे तक सुलभ बैंकिंग का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

4. NCERT ने नई दिल्ली में बाल वाटिका चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और अन्य लॉन्च करके 65वां स्थापना दिवस मनाया।

हाल ही में 1 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के अनुरूप आधारभूत, डिजिटल और समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के तहत प्रमुख पहलों का अनावरण किया गया।

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSE&L) के सचिव संजय कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण, बाल वाटिका नामक एक समर्पित पीएम ई-विद्या DTH चैनल (चैनल संख्या 35) का शुभारंभ था, जो 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक ऑडियो-विजुअल सामग्री प्रदान करता है।

• उन्नत DIKSHA 2.0 प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया, जो संरचित पाठ, अनुकूली मूल्यांकन और प्रदर्शन फीडबैक प्रदान करता है, जिसमें एआई-संचालित विशेषताएं जैसे रीड अलाउड, क्लोज्ड कैप्शनिंग और 12 भारतीय भाषाओं में स्वचालित अनुवाद शामिल हैं, जिससे समावेशी, डिजिटल-प्रथम शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।

• NCERT ने दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान के लिए एक उन्नत पूर्व-मूल्यांकन स्क्रीनिंग टूल, प्रशस्त 2.0 भी प्रस्तुत किया है; यह टूल प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई और सहायता सुनिश्चित करने के लिए UDISE+, APAAR और स्वावलंबन कार्ड जैसे राष्ट्रीय पोर्टलों के साथ सहजता से एकीकृत है।

Key Points:-

(i) इस गति को और बढ़ाते हुए, संस्थान ने नई दिल्ली में अरबिंदो मार्ग पर स्थित अपने नए प्रवेश परिसर का उद्घाटन किया, हिंदी, संस्कृत, हो-हिंदी और कोया भाषाओं में प्राइमर प्रकाशित किए, एक केंद्रीकृत शिक्षण गेटवे के रूप में PM eVidya मोबाइल ऐप लॉन्च किया और चार NCERT प्रदर्शन स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी (VR) लैब स्थापित कीं।

(ii) NCERT ने कक्षा 1 और 2 के लिए समावेशी पाठ्यपुस्तकें बनाने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग पर आधारित एक पहल, किताब एक पढ़े अनेक, और उत्कल जननींकर सुजोग्य संताना का विमोचन किया, जो राज्य और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले 100 उल्लेखनीय ओडिया हस्तियों की रूपरेखा वाली एक पुस्तक है; इसके अतिरिक्त, PSSCIVE ने कौशल-आधारित शिक्षा पर NEP 2020 के फोकस के साथ संरेखित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर पदाधिकारियों के लिए एक पुस्तिका लॉन्च की।

(iii) NEP 2020 के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, NCERT ने शिक्षा सुधार में अपने नेतृत्व की पुष्टि की, जिसमें स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) और फाउंडेशनल स्टेज फ्रेमवर्क (NCF -FS 2022) जैसे अपने हालिया योगदानों का हवाला दिया, और खुद को प्रणालीगत परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में स्थापित किया।

INTERNATIONAL

1. अभ्यास मैत्री 2025: भारत और थाईलैंड ने मेघालय में 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया।

भारतीय सेना (IA) और रॉयल थाई आर्मी (RTA) के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, "मैत्री अभ्यास" का 14वां संस्करण 1 सितंबर, 2025 को मेघालय के उमरोई स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड (FTN) में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 सितंबर, 2025 तक जारी रहेगा और आतंकवाद विरोधी और शांति अभियानों पर केंद्रित रहेगा।

- **मैत्री अभ्यास पहली बार 2006 में शुरू किया गया था और इसे भारत और थाईलैंड बारी-बारी से आयोजित करते हैं। संस्कृत और थाई दोनों भाषाओं में "मैत्री" शब्द का अर्थ "मित्रता" होता है, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है।**

- **13वें संस्करण का आयोजन थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्राकन में किया गया।**

- **इस वर्ष के अभ्यास में अर्ध-शहरी और जंगली इलाकों में आतंकवाद-रोधी और उग्रवाद-रोधी अभियानों में सामरिक समन्वय पर ज़ोर दिया गया है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति स्थापना मानकों के अनुरूप भी है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ाते हुए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मज़बूत करना है।**

Key Points:-

(i) अभ्यास मैत्री 2025 में दोनों पक्षों की पैदल सेना की टुकड़ियाँ भाग ले रही हैं, जिनमें प्रत्येक टुकड़ी में लगभग 50-76 सैनिक शामिल हैं। ये अभ्यास हिंद-प्रशांत और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करते हुए संयुक्त निर्णय लेने, योजना बनाने और अभियानों को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

(ii) इस संस्करण में प्रशिक्षण गतिविधियों में ड्रोन और काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन, जंगल युद्धाभ्यास, लाइव फायरिंग अभ्यास, क्लोज़-क्वार्टर युद्ध प्रशिक्षण, और बंधक बचाव, निकासी अभ्यास, और घेराबंदी और तलाशी अभियान सहित मिशन सिमुलेशन जैसी आधुनिक रणनीतियों का उपयोग शामिल है। ये अभ्यास युद्ध की तैयारी और समन्वय को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण हैं।

(iii) इस संस्करण का महत्व इस तथ्य से चिह्नित है कि भारत पांच साल के अंतराल के बाद अभ्यास मैत्री की मेजबानी कर रहा है, आखिरी बार 2019 में अभ्यास मैत्री की मेजबानी की गई थी। यह ASEAN देशों के साथ सैन्य साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

BANKING & FINANCE

1. भारत में हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए SBI और AFD ने 100 मिलियन यूरो की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए।

30 अगस्त, 2025 को, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और एजेंसी फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (AFD) ने गुजरात के गांधीनगर स्थित SBI की GIFT सिटी शाखा में €100 मिलियन (लगभग ₹900 करोड़) के ऋण-व्यवस्था (LoC) समझौते को औपचारिक रूप दिया। इस सहयोग का उद्देश्य जलवायु शमन और अनुकूलन परियोजनाओं को समर्थन देकर भारत को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलने में तेज़ी लाना है।

• इस ऋण सहायता से प्राप्त धनराशि का उपयोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाने वाली पहलों पर किया जाएगा। SBI ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, 2030 तक अपने हरित ऋण पोर्टफोलियो को अपने घरेलू अग्रिमों के 7.5-10% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

• यह साझेदारी SBI को हरित प्रौद्योगिकी, परियोजना संरचना और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रथाओं में AFD की वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाने की भी अनुमति देती है।

Key Points:-

(i) जून 2025 तक, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, SBI के पास ₹54.7 लाख करोड़ से अधिक की जमा राशि है। बैंक सतत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय और विकास वित्त संस्थानों से सक्रिय रूप से ऋण राशि जुटा रहा है। AFD के साथ इस सहयोग के माध्यम से, SBI का लक्ष्य अपने हरित वित्त रोडमैप को आगे बढ़ाना और पूरे भारत में प्रभावशाली जलवायु समाधानों को सक्षम बनाना है।

(ii) समझौते को 30 अगस्त, 2025 को गुजरात के गांधीनगर में SBI की GIFT सिटी शाखा में अंतिम रूप दिया गया।

(iii) यह रणनीतिक कदम सतत विकास के वित्तपोषण और 2030 तक अपने घरेलू सकल अग्रिमों का 7.5-10% बनाने वाले हरित पोर्टफोलियो को प्राप्त करने के लिए SBI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। साझेदारी स्थिरता के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती है।

2. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 8वां स्थापना दिवस मनाया, 12 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार किया।

1 सितंबर, 2025 को, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) - डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत एक भुगतान बैंक - ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका मिशन "किसी भी समय, कहीं भी, आपके दरवाजे पर बैंकिंग" प्रदान करना था, जिसने देश भर में 12 करोड़ ग्राहक खातों को पार कर लिया।

• इस अवसर पर, IPPB ने अपने डोरस्टेप बैंकिंग मॉडल की सफलता पर प्रकाश डाला, जो लगभग 1.64 लाख डाकघरों और 1.9 लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से हासिल किया गया है, जिससे वे प्रभावी रूप से "दरवाजे पर बैंकर" बन गए हैं और भारत के दूरदराज के कोनों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार हुआ है।

• IPPB ने कागज रहित, सुरक्षित और निर्बाध बैंकिंग पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजीस्मार्ट (डिजिटल बचत खाते), प्रीमियम आरोग्य बचत खाता (वित्तीय सेवाओं को स्वास्थ्य लाभ से जोड़ना) और आधार-

आधारित चेहरा प्रमाणीकरण जैसे डिजिटल समाधान प्रदान करके अपनी सेवाओं में लगातार नवाचार को एकीकृत किया है।

• इस अवसर पर बोलते हुए IPPB की अध्यक्ष सुश्री वंदिता कौल ने इस बात पर जोर दिया कि IPPB ने 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को सशक्त बनाकर वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण को एक ठोस वास्तविकता में बदल दिया है, इस कदम को उन्होंने "सभी के लिए दरवाजे पर बैंकिंग" के रूप में वर्णित किया।

Key Points:-

(i) IPPB के MD और CEO डॉ. आर. विश्वेश्वरन ने बैंक की यात्रा पर विचार किया और कहा कि लाखों करोड़ रुपये के लेनदेन डोरस्टेप मॉडल के माध्यम से हुए हैं, जो एक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में IPPB की उभरती भूमिका को रेखांकित करता है।

(i) IPPB अपने नौवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसने न केवल अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने, बल्कि डिजिटल समावेशन और नवाचार को भी गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिससे अंतिम-मील बैंकिंग वितरण में वैश्विक बेंचमार्क के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

ECONOMY & BUSINESS

1. अगस्त में भारत का GST संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन रुपये हो गया।

हाल ही में, 1 सितंबर, 2025 को, भारत सरकार ने घोषणा की कि अगस्त के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ₹1.86 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित यह वृद्धि निरंतर घरेलू आर्थिक गति और मज़बूत कर अनुपालन को दर्शाती है।

• अगस्त में ₹1.86 लाख करोड़ (₹1.86 ट्रिलियन) का सकल GST राजस्व मज़बूत आंतरिक खपत और मूल्य निर्धारण क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि पूरी वृद्धि आयात के बजाय घरेलू स्रोतों से हुई है, जिससे कर आधार में सुधार को बल मिला है। पिछले महीने की तुलना में, जुलाई का जीएसटी संग्रह ₹1.95-1.96 लाख करोड़ रहा, जो अगस्त में थोड़ी धीमी वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन फिर भी मज़बूत मासिक प्रदर्शन के अनुरूप है।

• वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिनके पास कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भी है, ने कैबिनेट चर्चा के दौरान अगस्त के संग्रह पर प्रकाश डाला, जिससे अगली पीढ़ी के GST सुधारों को आगे बढ़ाने के सरकार के संकल्प को बल मिला।

Key Points:-

(i) आर्थिक लचीलेपन को मज़बूत करने वाले GST राजस्व संग्रह 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली 56वीं GST परिषद की बैठक से पहले विशेष रूप से

महत्वपूर्ण हैं। कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने और अनुपालन को सुव्यवस्थित करने सहित प्रमुख सुधार प्रस्ताव एजेंडे में हैं।

(ii) GST का बेहतर प्रदर्शन GST 2.0 के तहत राज्यों के लिए अनुमानित लाभ का समर्थन करता है, SBI रिसर्च का अनुमान है कि नए सुधार ढांचे के तहत चालू वित्त वर्ष में राज्यों का राजस्व 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

(iii) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) राजस्व दक्षता को और बढ़ाने के लिए GST प्रशासन में तकनीकी संवर्द्धन - जैसे ई-इनवॉयसिंग और वास्तविक समय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) समाधान - को लागू करना जारी रखे हुए है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. सरकार ने तत्काल प्रभाव से टी.सी.ए. कल्याणी को 29वें महालेखा नियंत्रक (CGA) के रूप में नियुक्त किया है।

1 सितंबर, 2025 को, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी को 29वीं महालेखा नियंत्रक (CGA) नियुक्त करने की घोषणा की। भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS) की 1991 बैच की अधिकारी, वह श्री एस.एस. दुबे का स्थान लेंगी, जो मार्च 2023 से इस पद पर कार्यरत थे। यह नियुक्ति सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मज़बूत करने और सरकारी लेखांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- **श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा हैं, जहाँ उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में बी.ए. की उपाधि प्राप्त की और अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक अर्जित किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्नातकोत्तर उपाधि और पश्चिमी यूरोपीय अध्ययन में एम.फिल. की उपाधि प्राप्त की।**

- **अपने तीन दशकों से भी अधिक के शानदार करियर में, कल्याणी ने रक्षा, वित्त, दूरसंचार, उर्वरक, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण सहित विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और शासन में उनका व्यापक अनुभव सरकारी कार्यों में सुधारों को आगे बढ़ाने और दक्षता बढ़ाने में सहायक रहा है।**

- **मुख्य वित्तीय सलाहकार के रूप में, कल्याणी सरकार के लेखा कार्यों की देखरेख करेंगी, जिसमें संसद के लिए केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रबंधन और राजकोषीय विवेकशीलता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल है। उनके नेतृत्व से भारत की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को और मज़बूती मिलने और सरकारी लेखांकन में नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।**

Key Points:-

(i) अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, कल्याणी गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थीं। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने मंत्रालय के वित्तीय कार्यों के प्रबंधन और वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(ii) टी.सी.ए. कल्याणी सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रबल समर्थक रही हैं। उल्लेखनीय है कि उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना की पहल का नेतृत्व किया, जिससे किसानों को उर्वरक खरीद सहायता की सुविधा मिली और इस प्रकार डिजिटल शासन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।

(iii) श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी की 29वीं महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति, भारत की बेहतर वित्तीय शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने व्यापक अनुभव और सुधार के प्रति समर्पण के साथ, वे देश की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने, अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

SPORTS

1. भारत पिकलबॉल विश्व कप 2025 में पहली बार अपनी टीम भेजेगा, जिससे वैश्विक खेल उपस्थिति मजबूत होगी।

31 अगस्त, 2025 को, युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) के तहत कार्यरत भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (IPA) ने घोषणा की कि भारत पिकलबॉल विश्व कप 2025 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पहली टीम भेजेगा। यह ऐतिहासिक कदम वैश्विक प्रतिस्पर्धी पिकलबॉल में भारत के प्रवेश को चिह्नित करता है, जो उभरते खेलों पर देश के बढ़ते फोकस को उजागर करता है।

- **भारत की टीम ग्लोबल पिकलबॉल फेडरेशन (GPF) के तत्वावधान में फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2025 में भाग लेगी।**

- **टीम में 14 सदस्यीय टीम शामिल है, जिसे ओपन, अंडर-16 और +50 सहित कई श्रेणियों में चुना गया है। इस चयन में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलित प्रतिनिधित्व पर ज़ोर दिया गया है ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।**

- **भारतीय पिकलबॉल टीम प्रशिक्षण और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगी। भारत ग्लोबल पिकलबॉल अलायंस में शामिल हो रहा है, जो एक ऐसा गठबंधन है जिसमें एसोसिएशन ऑफ पिकलबॉल प्लेयर्स (APP, USA), कैनेडियन नेशनल पिकलबॉल लीग (CNPL), यूरोपियन पिकलबॉल फेडरेशन (EPF), नेशनल पिकलबॉल लीग (NPL, ऑस्ट्रेलिया) और पिकलबॉल डी-जॉय (वियतनाम) शामिल हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक प्रतियोगिताओं का मानकीकरण करना और पिकलबॉल को दुनिया भर में एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देना है।**

Key Points:-

(i) इस आयोजन में भागीदारी भारत को अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने, उन्नत तकनीकों का अन्वेषण करने और देश में पिकलबॉल के लिए जमीनी स्तर पर विकास पहलों को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करती है। आईपीए इस अवसर का सक्रिय रूप से उपयोग प्रतिभा खोज और कौशल विकास के लिए संरचित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और घरेलू लीग

तैयार करने में कर रहा है।

(ii) यह ऐतिहासिक समावेश, खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसी एमवाईएएस पहलों के तहत उभरते खेलों को बढ़ावा देने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप भी है, जो प्रदर्शन-आधारित मान्यता, युवा जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय खेल कूटनीति पर ज़ोर देता है। भारत की भागीदारी से देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और खेल क्लबों में पिकलबॉल में युवाओं की रुचि और भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

(iii) यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के लिए दुनिया के पहले पेशेवर वैश्विक पिकलबॉल दौरे में योगदान करने का मंच तैयार करता है, जो 2026 में शुरू होने वाला है। इन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में भारत की भागीदारी स्थायी पेशेवर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उभरते विषयों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2. भारत ने कजाकिस्तान में 2025 में होने वाली 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 50 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

भारत ने 16 से 30 अगस्त तक कज़ाकिस्तान के श्यामकेंट शूटिंग प्लाज़ा में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। रिकॉर्ड तोड़ पदक तालिका के साथ, भारत ने सीनियर और जूनियर दोनों निशानेबाजी स्पर्धाओं में सभी प्रतिभागी देशों को पछाड़ दिया।

- **भारत के 35 सीनियर निशानेबाजों और 129 जूनियर निशानेबाजों के दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 99 पदक जीते, जिनमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। यह पहली बार था जब भारत एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।**

- **इस चैंपियनशिप में एशिया के 27 देशों के 748 एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिससे यह महाद्वीपीय स्तर पर निशानेबाजी के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी मंचों में से एक बन गया। भारत के प्रभुत्व ने सटीक खेलों में उसकी बढ़ती ताकत को उजागर किया।**

Key Points:-

(i) कजाकिस्तान ने 21 स्वर्ण, 24 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ कुल 70 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 37 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, उसके बाद कोरिया 55 और ईरान 17 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

(ii) इस चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई निशानेबाजी परिसंघ (ASC) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) और कजाकिस्तान निशानेबाजी खेल महासंघ के साथ साझेदारी में किया गया था, जिससे प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष खेल के वैश्विक स्तर के मानकों को सुनिश्चित किया गया।

(iii) इस आयोजन ने न केवल एशिया में भारत की खेल प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) की पहल के माध्यम से जमीनी स्तर के निशानेबाजी विकास कार्यक्रमों और सरकारी समर्थन की सफलता को भी रेखांकित किया।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को "जीवन के वृक्ष" के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

हाल ही में, 2 सितंबर, 2025 को, एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय (APCC) की स्थापना के उपलक्ष्य में, विश्व नारियल दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया। 2009 में पहली बार मनाया गया यह दिवस दुनिया भर में कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य और आजीविका में नारियल के अपार योगदान का सम्मान करता है।

• एक, उत्पत्ति और महत्व: विश्व नारियल दिवस की शुरुआत APCC द्वारा की गई थी - जो नारियल उत्पादक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंतर-सरकारी निकाय है - जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है; यह APCC की स्थापना तिथि के साथ मेल खाते हुए 2 सितंबर को मनाया जाता है।

• दो, पहली बार 2009 में मनाया गया: विश्व नारियल दिवस का उद्घाटन 2009 में नारियल प्रदर्शनियों, किसान कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ था, जिसका उद्देश्य "जीवन के वृक्ष" के पारिस्थितिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मूल्य को उजागर करना था।

Key Points:-

(i) तीन, वैश्विक पहुंच और उद्देश्य: अपनी स्थापना के बाद से, यह दिवस एशिया-प्रशांत से अन्य क्षेत्रों में फैल गया है, तथा टिकाऊ खेती, खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और पर्यावरण-उत्पादों में नारियल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है।

(ii) चौथा, अनुसंधान और लचीलेपन पर भारत का ध्यान: इस वर्ष असम में, नारियल विकास बोर्ड (CBD) ने "नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना" विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें वैज्ञानिक खेती, फसल की गुणवत्ता, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों और आजीविका के अवसरों पर चर्चा की गई, जिसमें नारियल क्षेत्र में सतत नवाचार पर असम के जोर को उजागर किया गया।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. प्राइमा एयरोस्पेस के अर्जुन ड्रोन को DGCA टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिससे भारत के कृषि-तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिला।

28 अगस्त, 2025 को, सलाम किसान प्लेटफ़ॉर्म बनाने वाली प्राइमा ग्रुप की तकनीकी शाखा, प्राइमा एयरोस्पेस को अपने अर्जुन कृषि ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। यह पूरे भारत में ड्रोन-

संचालित कृषि को स्वदेशी रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

• PRYMA एयरोस्पेस ने 28 अगस्त, 2025 को अर्जुन ड्रोन के लिए DGCA टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, जबकि इसके ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को DGCA-प्रमाणित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) के रूप में मान्यता दी गई। यह दोहरी स्वीकृति सलाम किसान के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से ड्रोन निर्माण, पायलट प्रशिक्षण और ऑन-फील्ड तैनाती के लिए एक एकीकृत मार्ग को सक्षम बनाती है।

• सलाम किसान पहल के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में, PRYMA ने पहले ही 3,00,000 से ज़्यादा किसानों को ड्रोन छिड़काव और सटीक कृषि समाधानों से सशक्त बनाया है। DGCA के समर्थन से, अर्जुन ड्रोन का अब पूरे भारत में विस्तार किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण कृषि में एक सुरक्षित, सुलभ और विनियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी।

Key Points:-

(i) विदेशी आयात के विपरीत, अर्जुन ड्रोन को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से महाराष्ट्र के जलना स्थित प्रायमा (PRYMA) के 20,000 वर्ग फुट के अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इससे बेहतर स्थानीयकरण, निरंतर बिक्री पश्चात सेवा, कम डाउनटाइम और सलाम किसान के डिजिटल ढांचे में सहज एकीकरण सुनिश्चित होता है।

(ii) यह प्रमाणन फ्रैंचाइज़ी संचालकों, वितरकों और संस्थागत ग्राहकों—जिनमें बागान, विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) से जुड़ी पहल शामिल हैं—के लिए अर्जुन को अपनाने के नए रास्ते खोलता है। यह स्केलेबल मॉडल प्रशिक्षित ग्रामीण पायलटों, कृषि-उद्यमियों और युवा रोज़गार के अवसर पैदा करता है, जो आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि प्रौद्योगिकी विकास जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

(iii) इससे पहले 2025 में, PRYMA ग्रुप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान महाराष्ट्र सरकार के साथ ₹300 करोड़ के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। अब DGCA प्रमाणन प्राप्त होने के साथ, ये प्रतिबद्धताएँ ठोस पहल बन रही हैं, जो ड्रोन-आधारित कृषि परिवर्तन के लिए सरकार के दृष्टिकोण में फर्म की भूमिका को और मज़बूत कर रही हैं।

2. BHEL ने फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम्स के निर्माण के लिए DMRL हैदराबाद के साथ LAToT पर हस्ताक्षर किए।

30 अगस्त, 2025 को, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत, हैदराबाद स्थित रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (DMRL) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु एक लाइसेंस समझौते (LAToT) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता BHEL को मिसाइल प्रणालियों के लिए फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम बनाने का अधिकार देता है, जिससे भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताएँ मज़बूत होंगी।

• LAToT, BHEL को फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम्स का उत्पादन करने की अनुमति देता है, जो DMRL द्वारा विकसित कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग एंड सिंटरिंग (CIP-S) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, विद्युत

चुम्बकीय संकेतों के सटीक संचरण को सुनिश्चित करते हुए मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों में रडार एंटेना की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

• रडार डोम या रेडोम संवेदनशील रडार घटकों को गर्मी, धूल और नमी जैसी पर्यावरणीय स्थितियों से बचाते हैं, साथ ही उच्च सिग्नल निष्ठा बनाए रखते हैं, जिससे वे सीकर-आधारित मिसाइल और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं।

Key Points:-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी BHEL, इन उच्च परिशुद्धता वाले रेडोमों का घरेलू स्तर पर विनिर्माण करने के लिए अपनी उन्नत उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करेगी, जिससे आयातित रक्षा घटकों पर भारत की निर्भरता कम होगी।

(ii) फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम का स्वदेशी उत्पादन न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है, बल्कि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत करता है, कुशल रोजगार के अवसर पैदा करता है, और रक्षा विनिर्माण के लिए "मेक इन इंडिया" पहल में योगदान देता है।

(iii) इस साझेदारी से DRDO प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच आगे सहयोग का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे मिसाइलों, रडार और एयरोस्पेस प्रणालियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास संभव होगा, जिससे महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।

3. DRDO ने भारतीय नौसेना को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए नौसेना फ्लेयर प्रणाली प्रदान की।

29 अगस्त, 2025 को, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पुणे स्थित अपनी उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (HEMRL) के माध्यम से भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए एक स्वदेशी सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास और वितरण किया। यह प्रगति नौसेना रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर प्रणाली को DRDO के पुणे स्थित HEMRL द्वारा विकसित किया गया और पुणे में आयोजित एक समारोह में नौसेना आयुध निरीक्षण महानिदेशक (DG-NAI), रियर एडमिरल रूपक बरुआ को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। यह आपूर्ति स्वदेशी नवाचार के माध्यम से भारत की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने की DRDO की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

• फ्लेयर प्रणाली को पानी के अंदर पायरोटेक्निक संचार उपकरण के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पनडुब्बियों को संचालन के दौरान सतह पर संकेत देने में मदद मिलती है।

• पनडुब्बी के सिग्नल इजेक्टर से बाहर निकलने पर, फ्लेयर जल स्तंभ के माध्यम से ऊपर उठता है और सतह पर पहुंचने पर प्रज्वलित हो जाता है, जिससे उच्च तीव्रता वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो

प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी लंबी दूरी तक दिखाई देता है।

Key Points:-

(i) सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर दोहरे रंग की सिग्नलिंग क्षमता प्रदान करता है। लाल सिग्नल संकट या आपातकालीन स्थितियों का संकेत देते हैं, जबकि हरे सिग्नल बेड़े के युद्धाभ्यास के दौरान पहचान, पहचान या सुरक्षित-संचालन संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा नौसेना की संपत्तियों के बीच सामरिक संचार और समन्वय को बढ़ाती है।

(ii) उच्च जलमग्न दबावों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए फ्लेयर को दबाव-प्रतिरोधी आवरण में रखा गया है। इसका हाइड्रोस्टेटिक तंत्र सतह पर फ्लेयर को सक्रिय करता है, जिससे सामरिक आवश्यकताओं के आधार पर चमकीले लाल या हरे रंग के स्टार सिग्नल उत्पन्न होते हैं। इस प्रणाली का डिज़ाइन चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में स्थायित्व और कार्यक्षमता पर ज़ोर देता है।

(iii) सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर प्रणाली का सफल विकास और वितरण भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह प्रगति न केवल भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को मज़बूत करती है, बल्कि विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करने के राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देती है।

Static GK

Gujarat	मुख्यमंत्री: भूपेन्द्र पटेल	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
Thailand	राजधानी: बैंकॉक	मुद्रा: थाई बाट
SBI	अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	मुख्यालय: मुंबई
Ministry of Youth Affairs & Sports (MYAS)	कैबिनेट मंत्री: मनसुख मंडाविया	मुख्यालय: नई दिल्ली
Controller General of Accounts (CGA)	स्थापना: 1975	मुख्यालय: नई दिल्ली
BHEL	स्थापना: 1964	मुख्यालय: नई दिल्ली
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली